

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन

¹डॉ० संजय कुमार स्वर्णकार, ²डॉ० सुषमा वर्मा

¹असिस्टेंट प्रोफेसर, बी० एड० विभाग, उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी।

²सहायक अध्यापिका, यू० पी० एस० मंचितपुर, अमावां, रायबरेली।

¹Email- drsanjay0082@gmail.com



Received 07 August 2026

Accepted 12 August 2026

Published 26 August 2026

Corresponding Author:

डॉ० संजय कुमार स्वर्णकार

Email: drsanjay0082@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.64880/pcjaict.v1i4.11>

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s).



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

OPEN ACCESS

सारांश :

डिजिटल तकनीक आज विकास और प्रगति का मूल आधार बन चुकी है परन्तु इसके लाभ समान रूप से समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुँच पाए हैं। ग्रामीण महिलाएँ, जो भौगोलिक तथा लैंगिक दोनों ही रूपों में हाशिए पर हैं, डिजिटल संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग में अनेक संरचनात्मक बाधाओं का सामना करती हैं। यह शोध-पत्र ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन के पारस्परिक सम्बन्ध का विश्लेषण करता है, प्रमुख अवरोधों की पहचान करता है, सफल पहलों का अध्ययन प्रस्तुत करता है, तथा भविष्य के लिए ठोस नीतिगत सुझाव प्रदान करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जब डिजिटल पहुँच को शिक्षा, प्रशिक्षण, सुलभता, और सामाजिक-सांस्कृतिक समर्थन से जोड़ा जाता है, तब यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक—तीनों स्तरों पर महिलाओं के सशक्तिकरण को गति देता है।

प्रमुख शब्दावली- डिजिटल समावेशन, सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन।

प्रस्तावना-

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, शासन, और सामाजिक सम्पर्क तक। इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल पहचान, ऑनलाइन लेन-देन, और ई-सेवाएँ अब ग्रामीण जीवन का भी हिस्सा बन रही हैं। फिर भी आँकड़े बताते हैं कि ग्रामीण और शहरी, तथा पुरुष और महिला के बीच डिजिटल पहुँच में बड़ा अंतर है। GSMA (2023) की रिपोर्ट

के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में लगभग 19% कम मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती हैं। भारत जैसे देशों में भी ग्रामीण महिलाओं की स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुँच शहरी महिलाओं से काफी पीछे है। यह लैंगिक डिजिटल विभाजन न केवल तकनीकी असमानता

How to Cite this article: स्वर्णकार, संजय कुमार एवं वर्मा, सुषमा. (2026). ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन. *The Paradigm Chronicle Journal of Academic Inquiry & Critical Thought* 1(4), Page No. 103-112.

DOI: <https://doi.org/10.64880/pcjaict.v1i4.11>

है, बल्कि यह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों को भी सीमित करता है। इसलिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल समावेशन का अर्थ है- सिर्फ तकनीक तक पहुँच नहीं, बल्कि उसके माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आत्मनिर्णय का अधिकार।

डिजिटल समावेशन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति- विशेषकर वंचित, ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर तथा तकनीकी रूप से पिछड़े वर्ग को डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, सूचना-संचार साधनों और संबंधित सेवाओं तक समान एवं प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की जाती है। यह केवल तकनीकी साधनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल साक्षरता, डिजिटल कौशल, डिजिटल सामग्री की उपलब्धता, तकनीक के उपयोग की क्षमता, भाषाई सरलता और तकनीक के सुरक्षित उपयोग की जागरूकता भी शामिल है। डिजिटल समावेशन का मूल लक्ष्य यह है कि कोई भी व्यक्ति डिजिटल क्रांति से पीछे न छूटे और समाज के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल संसाधनों का न्यायपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। डिजिटल समावेशन यह मान्यता रखता है कि तकनीक सामाजिक और आर्थिक उन्नति का माध्यम है, अतः उसका लाभ केवल शहरी या संपन्न वर्ग तक सीमित न हो, बल्कि ग्रामीण आबादी, महिलाओं, कमजोर वर्गों और दिव्यांग समुदाय तक भी पहुँचे। इस अवधारणा के तहत इंटरनेट की सुलभता, किफायती दरों पर मोबाइल डेटा, स्थानीय भाषा आधारित डिजिटल सामग्री, डिजिटल शिक्षा और ई-सेवाओं की उपलब्धता को व्यापक महत्व दिया जाता है।

डिजिटल समावेशन का क्षेत्र केवल सुविधा प्रदान करने से व्यापक है; यह सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक डिजिटल रूप से सक्षम हो सके, चाहे वह भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्र में रहता हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो या सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्ग से संबंधित हो। डिजिटल समावेशन ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन उद्यमिता, डिजिटल भुगतान प्रणाली और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण को जीवन के हर क्षेत्र में सुगमता से उपलब्ध करवाने पर बल देता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का नया आयाम प्रस्तुत करता है, क्योंकि डिजिटल तकनीक के माध्यम से लोग सीधे सरकारी योजनाओं से लाभ ले सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने उत्पाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और वित्तीय लेन-देन सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। डिजिटल समावेशन के बिना “डिजिटल इंडिया” का लक्ष्य अधूरा है, क्योंकि समावेशन ही तकनीक को जन-तकनीक बनाता है। अतः डिजिटल समावेशन की अवधारणा एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है जो समाज में समानता, अवसरों का विस्तार, सूचना तक पहुँच और जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लैंगिक डिजिटल विभाजन का परिप्रेक्ष्य- डिजिटल प्रौद्योगिकी ने वैश्विक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वित्तीय समावेशन और शासन-प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, लेकिन इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। विशेषकर महिलाएँ तकनीक तक पहुँच, उपयोग, डिजिटल साक्षरता, और डिजिटल आर्थिक अवसरों के मामले में पुरुषों की तुलना में पीछे हैं। इसी असमानता को लैंगिक डिजिटल विभाजन कहा जाता है। यह विभाजन केवल तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक असमानताएँ, शिक्षा का स्तर, सुरक्षा चिंताएँ और सांस्कृतिक बाधाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य- विश्व स्तर पर इंटरनेट उपयोग में पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी लैंगिक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की रिपोर्टों के अनुसार-

- विश्व स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की इंटरनेट पहुँच लगभग 12% कम है।
- अफ्रीका और दक्षिण एशिया वे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं की डिजिटल पहुँच सबसे कम है।
- वैश्विक स्तर पर महिलाओं की डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँच भी पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि डिजिटल परिवर्तन का लाभ महिलाओं को समान रूप से नहीं मिल रहा है, और परिणामस्वरूप वे वैश्विक सूचना-समाज में सीमित भूमिका निभा रही हैं।

भारत में लैंगिक डिजिटल विभाजन की स्थिति- भारत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल जनसंख्या आधार वाला देश बन चुका है, लेकिन लैंगिक डिजिटल विभाजन यहाँ एक गंभीर चुनौती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार लैंगिक डिजिटल विभाजन की भयावह स्थिति इस प्रकार है-

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO, 2022) के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 24% महिलाएँ इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 42% है।
- शहरी क्षेत्रों में स्थिति बेहतर है, लेकिन अंतर अभी भी मौजूद है- 33% महिलाएँ बनाम 57% पुरुष।
- भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फोन स्वामित्व पुरुषों की तुलना में लगभग 30% कम है।
- साझा मोबाइल उपयोग के कारण गोपनीयता और स्वतंत्र उपयोग की कमी भी एक बड़ी बाधा है।
- PMGDISHA और अन्य कार्यक्रमों के बावजूद महिलाओं में डिजिटल साक्षरता का स्तर अभी भी सामाजिक रूढ़ियों और शिक्षा की कमी के कारण सीमित है।
- कई परिवारों में डिजिटल उपकरणों का उपयोग लड़कियों को जोखिमपूर्ण या अनावश्यक समझकर रोका जाता है।

ग्रामीण भारत में लैंगिक डिजिटल विभाजन की स्थिति- ग्रामीण क्षेत्र में यह विभाजन और अधिक गहरा और जटिल है।

- इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर।
- स्मार्टफोन की उच्च लागत।
- बिजली और नेटवर्क की अनियमित आपूर्ति।
- ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर अभी भी पुरुषों से कम है।
- डिजिटल साक्षरता केंद्र सीमित हैं।
- कई महिलाएँ डिजिटल उपकरणों को 'पुरुषों का काम' मानती हैं।
- कई ग्रामीण परिवारों में महिलाओं का मोबाइल उपयोग संदेह के साथ देखा जाता है।
- महिलाओं के ऑनलाइन होने को परिवार जोखिमपूर्ण मानता है।
- विवाह, घरेलू कार्य और परंपरागत भूमिकाओं के कारण डिजिटल सीखने का समय सीमित है।
- महिलाओं की स्वतंत्र आय कम होने से स्मार्टफोन खरीदना संभव नहीं हो पाता।
- आर्थिक निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका कम होने से डिजिटल साधनों में निवेश कम होता है।
- ग्रामीण महिलाओं में UPI, मोबाइल बैंकिंग, और डिजिटल भुगतान का उपयोग पुरुषों की तुलना में बहुत कम है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लैंगिक डिजिटल विभाजन वैश्विक चुनौती है, लेकिन भारत—विशेष रूप से ग्रामीण भारत—में यह अधिक व्यापक और संरचनात्मक रूप से गहरा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ तभी संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है जब महिलाओं को समान अवसर, डिजिटल शिक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण, और तकनीकी संसाधन उपलब्ध हों। सरकारी नीतियाँ, सामुदायिक जागरूकता और महिला-उन्मुख डिजिटल कार्यक्रम इस विभाजन को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

डिजिटल सशक्तिकरण और ग्रामीण महिलाएँ- डिजिटल सशक्तिकरण का अर्थ है- तकनीक, इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल सेवाओं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक समान पहुँच प्रदान करना, ताकि व्यक्ति ज्ञान, सूचना, कौशल और संसाधनों का उपयोग कर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। भारत में डिजिटल क्रांति ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं- जैसे डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई-स्वास्थ्य सेवाएँ, ई-गवर्नेंस, और उद्यमिता से जुड़े डिजिटल साधन। जब ग्रामीण महिलाएँ मोबाइल फोन, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना सीखती हैं, तो वे सूचना के अभाव,

मध्यस्थों पर निर्भरता और सीमित गतिशीलता जैसी बाधाओं से मुक्त होकर अधिक आत्मनिर्भर बनती हैं। यह सशक्तिकरण केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति से जुड़ा है। इसलिए, डिजिटल सशक्तिकरण ग्रामीण महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक भागीदारी के नए अवसर प्रदान करता है।

डिजिटल तकनीक ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में कई परिवर्तन लाए हैं। अब वे मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से स्वयं वित्तीय लेन-देन कर सकती हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण, स्वयं सहायता समूह (SHG) प्रबंधन, और सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें सीधे ऑनलाइन मिल जाती है। 'दीक्षा', 'उमंग', 'नारी शक्ति पोर्टल', 'जन धन-आधार-मोबाइल (JAM)' जैसी डिजिटल पहलों ने उनके लिए सेवाओं को सरल और सुलभ बनाया है। कई ग्रामीण महिलाएँ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद बेचना सीख रही हैं, जिससे ग्राम-स्तरीय उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। हालांकि, डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएँ, उपकरणों की लागत और सामाजिक प्रतिबंध अभी भी चुनौतियाँ हैं। फिर भी, निरंतर प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और सरकारी पहल की मदद से ग्रामीण महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण तेजी से बढ़ रहा है, जो समावेशी और सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति और नागरिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ये नीतियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यमिता, डिजिटल प्रगति, सामाजिक सुरक्षा और गरीबों के उत्थान जैसे अनेक क्षेत्रों को कवर करती हैं। नीचे प्रमुख सरकारी नीतियों और योजनाओं को मुख्य क्षेत्रों के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है:

1. महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएँ-

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP): बालिकाओं के जन्म, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- महिला शक्ति केंद्र योजना: ग्रामीण महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास।
- वन स्टॉप सेंटर स्कीम: हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करना।
- उज्ज्वला योजना: महिलाओं की तस्करी रोकने और पुनर्वास में सहायता।

2. शिक्षा से संबंधित योजनाएँ-

- समग्र शिक्षा अभियान: स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020): शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार।
- मध्याह्न भोजन योजना (PM Poshan): पोषण के साथ स्कूली शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाना।
- SWAYAM, DIKSHA और e-Pathshala: डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना।

3. स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएँ-

- आयुष्मान भारत (PMJAY): गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर।
- जननी सुरक्षा योजना: सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना।
- POSHAN Abhiyaan: कुपोषण में कमी लाने के लिए व्यापक अभियान।

4. डिजिटल और तकनीकी समावेशन योजनाएँ-

- डिजिटल इंडिया मिशन: डिजिटल ढाँचा, डिजिटल सेवाएँ और डिजिटल साक्षरता का विस्तार।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA): ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना।
- BharatNet Project: ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना।

5. ग्रामीण विकास और आजीविका योजनाएँ-

- मनरेगा (MGNREGA): ग्रामीण रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- DAY-NRLM: ग्रामीण आजीविका मिशन, SHG के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G): ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराना।
- जल जीवन मिशन: हर घर को नल से जल उपलब्ध कराना।

6. कृषि और किसान कल्याण योजनाएँ-

- PM किसान सम्मान निधि: किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: फसल क्षति पर बीमा सुरक्षा।
- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: कृषि बुनियादी ढाँचे के निर्माण को प्रोत्साहन।
- e-NAM: राष्ट्रीय कृषि बाजार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।

7. आर्थिक समावेशन और वित्तीय सुरक्षा योजनाएँ-

- जन धन योजना (PMJDY): हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाना।
- अटल पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: छोटे उद्यमों के लिए बिना गारंटी के ऋण।
- स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया: उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहन।

8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएँ-

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन।
- स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छता, शौचालय और जनस्वास्थ्य सुधार।
- PM उज्ज्वला योजना: गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन।

ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी यह प्रक्रिया कई संरचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों से घिरी हुई है। ये बाधाएँ न केवल महिलाओं की डिजिटल पहुँच को सीमित करती हैं, बल्कि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में भी अवरोध उत्पन्न करती हैं। प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं-

1. डिजिटल अवसंरचना की कमी- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन का सबसे बड़ा अवरोध पर्याप्त तकनीकी अवसंरचना का अभाव है।

- कई गाँवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है या मोबाइल नेटवर्क अस्थिर रहता है।
- ब्रॉडबैंड, वाई-फाई, और फाइबर कनेक्शन की उपलब्धता सीमित है।
- बिजली की अनियमित आपूर्ति डिजिटल उपकरणों के उपयोग को और कठिन बनाती है।

यह कमजोर अवसंरचना महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है।

2. डिजिटल उपकरणों की सीमित उपलब्धता-

- ग्रामीण परिवारों में स्मार्टफोन का स्वामित्व अक्सर पुरुषों के हाथ में केंद्रित होता है।

- महिलाओं को अक्सर साझा मोबाइल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी गोपनीयता और स्वतंत्र उपयोग बाधित होता है।
- स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंटरनेट रिचार्ज की उच्च लागत महिलाओं के स्वामित्व को सीमित करती है।

इस प्रकार आर्थिक निर्भरता डिजिटल सीखने और उपयोग में बाधा बनती है।

3. डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर- ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल समावेशन में एक मुख्य बाधा डिजिटल साक्षरता की कमी है जैसे-

- अधिकांश महिलाएँ स्मार्टफोन संचालन, इंटरनेट ब्राउजिंग, UPI भुगतान, ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म भरना जैसी बुनियादी डिजिटल क्षमताओं में कमजोर हैं।
- प्रशिक्षण केंद्रों तक उनकी पहुँच सीमित है।
- डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक कारणों से अक्सर कम देखी जाती है।

यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई-गवर्नेंस तक उनकी पहुँच को सीमित कर देता है।

4. सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंध- ग्रामीण भारत में सामाजिक मान्यताएँ और लैंगिक रूढ़ियाँ डिजिटल समावेशन को गहराई से प्रभावित करती हैं जैसे-

- महिलाओं द्वारा मोबाइल उपयोग को परिवार में संदेह या संकोच की दृष्टि से देखा जाता है।
- कई परिवार लड़कियों/महिलाओं के इंटरनेट उपयोग को अनुचित या जोखिमपूर्ण मानते हैं।
- पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ (घरेलू कार्य, खेती, देखभाल के दायित्व) महिलाओं को डिजिटल सीखने के लिए समय नहीं देती।

ये सामाजिक संरचनाएँ महिलाओं को डिजिटल स्पेस से दूर करती हैं।

5. शिक्षा का निम्न स्तर-

- ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी कम है।
- कम शिक्षा के कारण तकनीकी शब्दावली और डिजिटल प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है।
- अंग्रेजी आधारित डिजिटल इंटरफेस भी ग्रामीण महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है।

यह शिक्षा-आधारित डिजिटल विभाजन महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण से दूर रखता है।

6. ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर खतरों का भय-

- महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर स्टॉकिंग, फेक प्रोफाइल, फोटो दुरुपयोग जैसी आशंकाओं का डर होता है।
- परिवार भी सुरक्षा कारणों से महिलाओं के इंटरनेट उपयोग को सीमित करते हैं।
- साइबर सुरक्षा जागरूकता की कमी डिजिटल मंचों पर महिलाओं की उपस्थिति को कम कर देती है।

सुरक्षा और गोपनीयता का यह भय डिजिटल समावेशन की राह में बड़ी बाधा बनता है।

7. आर्थिक निर्भरता और संसाधनों की कमी-

- कई ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं।
- डिजिटल उपकरण, इंटरनेट पैक, या प्रशिक्षण शुल्क उनके लिए वहन करना कठिन होता है।
- आर्थिक संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार भी अक्सर महिलाओं के पास नहीं होता।

यह आर्थिक बाधा डिजिटल दुनिया तक पहुँच को अनौपचारिक बनाती है।

8. सरकारी योजनाओं तक सीमित पहुँच- यद्यपि डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुँच के लिए कई सरकारी योजनाएँ मौजूद हैं, लेकिन—

- जानकारी का अभाव

- आवेदन प्रक्रिया का डिजिटल होना
- स्थानीय स्तर पर अपर्याप्त प्रशिक्षण
- सामाजिक कार्यकर्ताओं और पंचायतों का सीमित सहयोग

इन सबके कारण महिलाएँ योजनाओं का लाभ नहीं उठा पातीं।

9. भाषा और सामग्री का अभाव-

- अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेजी आधारित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण और सामग्री का अभाव है।
- महिलाओं के लिए स्वरूपित अध्ययन सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार की भाषायी बाधाएँ डिजिटल पहुँच को सीमित कर देती है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं का डिजिटल समावेशन कई परतों वाली चुनौतियों से बाधित है- तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक। इन बाधाओं को दूर करने के लिए बहु-स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक है, जिसमें डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, महिला-उन्मुख प्रशिक्षण, सुरक्षित डिजिटल वातावरण, स्थानीय भाषा आधारित सामग्री और सामाजिक जागरूकता अभियान प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। जब तक ये बाधाएँ दूर नहीं होतीं, तब तक डिजिटल समावेशन वास्तविक सशक्तिकरण का माध्यम नहीं बन पाएगा।

ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल समावेशन हेतु नीतिगत सुझाव- ग्रामीण महिलाओं के डिजिटल समावेशन को बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियाँ आवश्यक हैं जो न केवल तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाएँ, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को भी दूर करें। भारत में डिजिटल परिवर्तन को स्त्री-समावेशी बनाने के लिए नीचे दिए गए नीतिगत सुझाव अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक माने जाते हैं।

1. डिजिटल अवसंरचना का विस्तार और सुलभता-

- ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर नेटवर्क, 4G/5G कनेक्टिविटी, और स्थिर ब्रॉडबैंड को प्राथमिकता दी जाए।
- दूरस्थ क्षेत्रों में सामुदायिक इंटरनेट हब और पंचायत-आधारित डिजिटल केंद्र स्थापित किए जाएँ।
- डिजिटल उपकरणों (स्मार्टफोन, टैबलेट) को महिलाओं हेतु सब्सिडी, ईएमआई योजना, या सरकारी वित्तीय सहायता के माध्यम से अधिक सुलभ बनाया जाए।

यह अवसंरचना सुधार महिलाओं के उपयोग के समय और स्थान संबंधी बाधाओं को कम करेगा।

2. महिला-केंद्रित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम-

- महिलाओं के लिए विशेष डिजिटल प्रशिक्षण शिविर, गाँव-स्तरीय कार्यशालाएँ, और लड़कियों के स्कूलों में डिजिटल क्लब शुरू किए जाएँ।
- सीखने की सामग्री को स्थानीय भाषाओं में तैयार किया जाए ताकि महिलाएँ तकनीक को सहजता से समझ सकें।
- प्रशिक्षण में मोबाइल बैंकिंग, UPI भुगतान, ऑनलाइन सरकारी सेवाएँ, साइबर सुरक्षा, और डिजिटल उद्यमिता जैसे व्यावहारिक विषय शामिल हों।
- प्रत्येक गाँव में महिला डिजिटल साथी (Digital Sakhi) की नियुक्ति की जाए जो अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित कर सके।

3. साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संरक्षण-

- महिलाओं के लिए विशेष साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन और स्थानीय जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

- स्कूलों, पंचायतों और महिला समूहों में साइबर अपराध, फेक प्रोफाइल, डाटा सुरक्षा, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि पर नियमित कार्यशालाएँ आयोजित हों।
- ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी महिलाओं को सरल भाषा में दी जाए।
- सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिला-उन्मुख सुरक्षा फीचर्स को बढ़ावा दिया जाए।

4. सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को कम करने हेतु पहल-

- पंचायत स्तर पर 'डिजिटल महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान' जैसी पहल शुरू की जाए।
- परिवारों, विशेषकर पुरुषों के लिए डिजिटल समावेशन पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिससे महिलाओं के डिजिटल उपयोग को स्वीकार्यता मिले।
- आंगनवाड़ी, स्वयं सहायता समूह (SHGs), और महिला मंडलों को डिजिटल सीखने के मंच के रूप में विकसित किया जाए।
- मीडिया और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से डिजिटल सीखने को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने का अभियान संचालित किया जाए।

5. आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े डिजिटल अवसर-

- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान, और ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाए।
- ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल माइक्रो-उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- सरकारी योजनाओं (जैसे PMEGP, NRLM, आदि) के डिजिटल आवेदन प्रक्रियाओं को सरल किया जाए ताकि महिलाएँ स्वयं आवेदन कर सकें।
- फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, डेयरी, कृषि-आधारित उद्यम आदि में डिजिटल तकनीक का उपयोग प्रोत्साहित किया जाए।

6. शिक्षा में डिजिटल समावेशन-

- ग्रामीण स्कूलों में बालिकाओं के लिए आईसीटी लैब, कंप्यूटर क्लास, और डिजिटल कंटेंट को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।
- किशोरियों के लिए 'डिजिटल स्किल प्रमाणपत्र' कार्यक्रम शुरू किए जाएँ, जो भविष्य में रोजगार में सहायक हों।
- ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन लर्निंग ऐप, SWAYAM आदि प्लेटफॉर्म की जानकारी गाँव स्तर पर पहुँचाई जाए।

7. सरकारी सेवाओं में डिजिटल पहुँच को सरल बनाना-

- सभी नागरिक सेवाओं जैसे आधार अपडेट, जनधन, राशन, स्वास्थ्य कार्ड, पेंशन इत्यादि के लिए स्थानीय डिजिटल सहायक केंद्र महिलाओं को प्रशिक्षित करें।
- डिजिटल सरकारी पोर्टलों को बहुभाषी बनाया जाए और प्रक्रियाएँ अत्यंत सरल की जाएँ।
- योजनाओं का लाभ भुगतान सीधे डिजिटल माध्यम से हो, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और स्वतंत्रता दोनों बढ़ें।

8. स्थानीय शासन और संस्थागत सहयोग-

- पंचायतों में एक डिजिटल महिला समन्वयक की नियुक्ति की जाए।
- राज्य सरकारें जिला स्तर पर महिला डिजिटल प्रगति निगरानी इकाई स्थापित करें।
- CSR फंडिंग और NGO साझेदारी के माध्यम से डिजिटल महिला हब विकसित किए जाएँ।

9. डिजिटल सामग्री का स्थानीयकृत और महिला-उन्मुख उत्पादन-

- महिला स्वास्थ्य, पोषण, कानून, शिक्षा, उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता से जुड़ी सामग्री स्थानीय भाषाओं और सरल प्रारूप में बनाई जाए।

➤ वीडियो-आधारित प्रशिक्षण, वॉइस-बेस्ड ऐप्स और इंटरैक्टिव टूल्स को प्राथमिकता दी जाए, जिससे कम-शिक्षित महिलाएँ भी सीख सकें।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं का डिजिटल समावेशन केवल तकनीकी हस्तक्षेप नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। डिजिटल अवसंरचना, प्रशिक्षण, सुरक्षा, आर्थिक अवसर, और सामाजिक समर्थन से ही महिलाओं की डिजिटल पहुँच बढ़ेगी। यदि उपरोक्त नीतिगत सुझावों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो डिजिटल इंडिया का लक्ष्य वास्तव में समावेशी और लैंगिक-संतुलित स्वरूप प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्ष- ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है, और डिजिटल समावेशन इस दिशा में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। डिजिटल तकनीक ने न केवल सूचना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाया है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय-क्षमता और सामाजिक भागीदारी को भी मजबूत किया है। ग्रामीण समाज में लंबे समय से मौजूद लैंगिक भेदभाव, सीमित संसाधन, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक प्रतिबंधों ने महिलाओं के अवसरों को सीमित किया था, परंतु डिजिटल साधनों ने इन बाधाओं को काफी हद तक कम करने का मार्ग प्रशस्त किया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सीखने ने महिलाओं को नए कौशल अर्जित करने, अपनी आय बढ़ाने और व्यापक समाज से जुड़ने में सक्षम बनाया है।

हालाँकि, इस प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ—जैसे डिजिटल साक्षरता का अभाव, सीमित कनेक्टिविटी, आर्थिक बाधाएँ, भाषाई अड़चनें, साइबर सुरक्षा जोखिम इत्यादि अभी भी डिजिटल समावेशन के पूर्ण लाभ में रुकावट बनती हैं। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सरकार, स्थानीय समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और तकनीकी कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित हो। डिजिटल प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास, महिला-केंद्रित योजनाएँ, सुरक्षित डिजिटल वातावरण और स्थानीय स्तर पर तकनीकी सहायता—इन सभी तत्वों का संयोजन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत जैसे देश में जहाँ ग्रामीण महिलाएँ कृषि, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा हैं, वहाँ डिजिटल समावेशन उनके विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अनिवार्य है। समग्र रूप से, डिजिटल समावेशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में अवसरों, संसाधनों और संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। यदि नीतिगत स्तर पर उचित दिशा-निर्देश, सहायक वातावरण और सतत प्रयास सुनिश्चित किए जाएँ, तो ग्रामीण महिलाएँ न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, बल्कि समाज में समान अधिकारों और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में भी सक्रिय योगदान दे सकती हैं। आने वाला समय डिजिटल तकनीक के माध्यम से महिलाओं के व्यापक, स्थायी और समावेशी सशक्तिकरण का युग साबित हो सकता है। इसलिए सरकार, निजी क्षेत्र, और नागरिक समाज—तीनों को मिलकर एक ऐसा डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना होगा जिसमें महिलाएँ सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि डिजिटल परिवर्तन की सह-निर्माता बनें।

संदर्भ सूची-

1. ILO इंडिया (2021). महिलाओं का श्रमबल सहभागिता—भारत अध्ययन (हिंदी).
2. UNDP भारत कार्यालय (2020). मानव विकास रिपोर्ट—भारत (हिंदी संस्करण).
3. जीएसएमए. (2023). द मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023।
4. डिजिटल एम्पावरमेंट फ़ाउंडेशन. (2023). कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर्स एनुअल रिपोर्ट।
5. नाबार्ड. (2023). सेल्फ हेल्प ग्रुप डिजिटल इजेशन प्रोग्राम रिपोर्ट।
6. नीति आयोग. (2021). भारत नवाचार सूचकांक 2021. नीति आयोग, भारत सरकार.
7. भारत की जनगणना (2011) – महिला संबंधी आँकड़े (हिंदी).
8. भारत सरकार. (2015). डिजिटल इंडिया प्रोग्राम रिपोर्ट. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY).
9. भारत सरकार (2018). राष्ट्रीय महिला नीति मसौदा 2018. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय.

10. भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.
11. भारत सरकार (2021). आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21. वित्त मंत्रालय.
12. भारती एयरटेल (2022). ई-शक्ति प्रोजेक्ट इम्पैक्ट रिपोर्ट।
13. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी, भारत सरकार (2024). डिजिटल इंडिया एन्नूयल रिपोर्ट।
14. यूएन वीमेन (2022). डिजिटल इनक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट्स।
15. यूएनडीपी (2025). डिजिटल टेक्नोलॉजी एज एन इन्स्ट्रुमेंट टू ब्रिज जेंडर गैप।
16. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) (2021). मुख्य निष्कर्ष (हिंदी). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
17. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (2022). स्वास्थ्य एवं सामाजिक खपत संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय.
18. वर्ल्ड बैंक (2024). ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड: वीमेन एंड डिजिटल डेवलपमेंट।
19. विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग (2024). डिजिटल आइडेंटिफिकेशन एंड वीमेन'स फ़ाइनेंशियल इन्क्लूजन।
20. विश्व बैंक भारत (2019). ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी रिपोर्ट (हिंदी).

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.